(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The liquidity position of the Company has been critical for quite some time which has affected the operations of the Company. To obviate the present liquidity crunch, Government is providing plan and non-plan funds, increase in cash credit limit with the banks and also inter corporate loans, etc.

Pension Scheme in the Public Sector Undertakings

1533. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have discontinued the pension scheme in the Public Sector Enterprises; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Gov ernment has decided that in respect of retirement benefits, Public Sector Enterprises should continue with the Contrinbutory Provident Fund Scheme. Individual Public Sector Enterprises may, if (they so desire, work out a suitable annuity scheme through the Life Insurance Corporation of India based on purely voluntary contributions by the employes, through a fund outside the Public Sector Enterprises and without any liability on the Public Sector Enterprises/Government .

Airborne Surveillance Warning and Control Project

1534. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have abandone the airborne Surveillance Warning and control (ASWAC) project, initiated in 1987; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) Under the ASWAC programme, Government had sanctioned certain competence build up activities in the area of airborne early warning technology, which have been completed. ,

विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रानिक मदों का उत्पादन

1535. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रानिक मदों का कुल कितना उत्पादन हुआ और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान इनका उत्पादन कितना होने का अनुमान है;

(ख) इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की घरेलू खपत और निर्यात का अनुपात क्या है और क्या यह सच है कि इन इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात में दक्षिण कोरिया और तैवान जैसे छोटे देश भारत से काफी आगे हैं यदि हां, तो भारत के इस मामले में पिछड़ने के या कारण हैं, और क्या इन्हें दूर करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि निर्यातोन्मुखी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने की एक योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा ठुकरा दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार उस पर पुनर्विचार करने के लिए योजना आयोग से अनुरोध करेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) पिछले तीन

दौरान इलैक्ट्रानिकी उद्योग के उत्पादन के क्षेत्रवार ब्यौरे तथा वर्ष 1994-95 के अनुमानित उत्पादन संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की स्वदेशी खपत के आंकड़े इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के आयात का एक बहुत बड़ा प्रतिशत "परियोजना आयात" के रूप में होता है, जिसमें इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को कोई अलग से नहीं दर्शाया जाता है। तथापि, वर्ष 1990-91 के दौरान कुल स्वदेशी उत्पादन की तुलना में निर्यात का अनुपात 9.5% है।

दक्षिण कोरिया तथा ताइवान जैसे देश इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात के मामले में भारत से बहुत आगे हैं, जिनका उत्पादन की तुलना में निर्यात का अनुपात 40% से भी अधिक है।

इस दिशा में भारत के पीछे रहने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(i) उत्पादन की अधिकतम क्षमता से कम उत्पादन होने के कारण उत्पादन की ऊंची लागत

(ii) स्वदेशी बिक्री की तुलना में निर्यात कम लाभकारी होना।

(iii) नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में अपर्याप्त जानकारी।

(iv) विदेशों में पर्याप्त विपणन स्रोतों का अभाव।

(ग) जी, नहीं।

सरकार द्वारा व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के संबंध में हाल ही में लिए गए उपायों के फलस्वरूप इन समस्याओं का समाधान हो जाने की संभावना है। व्यापार नीति में परिवर्तनों के कारण निर्यात की लाभकारिता में सुधार होने की सम्भावना है। यह आशा की जाती है कि नई औद्योगिक नीति से भारतीय उत्पादन इकाइयों का विलय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रचलन तक हो जाएगा तथा इसे प्रौद्योगिकी का अद्यतन और तेजी से होना संभव हो जाएगा। विदेशी व्यापार गृहों के प्रचलन से संबंधित प्रबंधनों के कारण विदेशों के बाजार में पदार्पण करने की स्थिति में सुधार हो सकता है।

विवरण

इलैक्ट्रानिकी उद्योग के उत्पादन संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरे:

(मूल्यों करोड़ रुपयों में)

उत्पादन का क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91	1994.95 (अनुमानित)
1. उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी	2650	2850	3000	8500
2. औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिकी	1000	1360	1370	3100
3. संचार तथा प्रसारण उपस्कर	1010	1560	1710	4500
4. सामरिक इलैक्ट्रॉनिकी	410	505	635	1200
5. कम्प्यूटर प्रणालियां	560	835	820	2800
6. संघटक-पुर्जे	1125	1520	1510	6500
7. गुप्त व्यापार क्षेत्र (हार्डवेयर)	160	215	275	1500
8. निर्यात के लिए साफ्टवेयर (निर्यात संसाधन क्षेत्र, शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों सहित)	115	165	220	2000
कुल	7030	9010	9540	30000